नॉट सो ईजी बिजनेस

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक- लवीश भंडारी (अर्थशास्त्री)

12 नवम्बर, 2018

''भारत द्वारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर प्रदर्शन दिखाना एक बड़ी खुशखबरी है और इसका स्वागत है। लेकिन अभी भी कई ऐसे शेष है जिनपर कार्य करने की आवश्यकता है।''

भारत के डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार काफी सराहनीय है और साथ ही यह हाल के सप्ताहों में कुछ सुखद समाचारों में से एक था। हांलाकि, अभी भी कुछ सवालों का जवाब जानना बाकी है जैसे कि सरकार ने क्या किया? यदि व्यापार सच में इतना आसान हो गया है, तो हमें नए व्यवसायों और निवेश में तेजी क्यों दिख रही हैं? निश्चित रूप से यदि हम भारत के लिए नीति प्राथमिकताओं के एक अधिक केंद्रित सेट को विकसित करने में मदद करना चाहते हैं तो हमारे लिए ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानना बेहद जरूरी हैं।

इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 100 से 77 तक का सफर रेटिंग में सुधार के साथ सहसंबंधित है, जो पिछले साल 6.6 प्रतिशत थी। यह लगातार दूसरा साल है जहाँ भारत ने अपनी रैंकिंग में काफी सुधार किया है, गौरतलब हो कि भारत ने पिछले साल 30 स्थानों की छलांग लगाई थी और इस साल 23 स्थानों की छलांग लगाते हुए अपनी रैंकिंग में सुधार की है। पिछले दो साल में, भारत की स्थिति 130 से 77 तक पहुँच गई है। 10 श्रेणियों से मिलकर बने इस इंडेक्स में भारत ने पिछले दो साल में आठ श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन दिखाया है और शेष बचे दो श्रेणियों में समान प्रदर्शन दिखाया है। इसके अलावा, एक और दिलचस्प बात यह थी कि निर्माण परमिट और सीमा पार व्यापार दो ऐसे पहलू थे जिसमें सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिले हैं; दोनों के लिए सूचकांक मूल्य क्रमशः 34 और 19 प्रतिशत बढ़ा है।

इसके साथ ही इज ऑफ डूइंग बिजनेस सर्वेक्षण के अनुसार, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां भारत ऐतिहासिक रूप से खराब प्रदर्शन करता आया है, लेकिन उन क्षेत्रों में भी भारत ने पिछले कुछ वर्षो में सकारात्मक सुधार किये हैं उदाहरण के लिए अनुबंधों का प्रवर्तन, कर चुकाना और संपत्ति पंजीकृत। इनमें से प्रत्येक बहु-क्षेत्रीय मुद्दे हैं जहां सरकार द्वारा परत दर परत समन्वित प्रयासों के साथ सुधार करना होगा और इसलिए, कानूनी और प्रक्रियात्मक परिवर्तन अधिक जटिल होंगे। अब, जबकि परिवर्तन की धीमी गति का कारण हमें ज्ञात हो चुका है, तो हमे यह तथ्य भी स्वीकार करना होगा कि ये ऐसे महत्त्वपूर्ण पहलू हैं जहां अधिक कार्रवाई की आवश्यकता होगी।

एक और सवाल है जो परेशान करता है कि क्या ऐसी रैंकिंग भारत में व्यापार की वास्तविकता को दर्शाती है? इस आलेख में लेखक ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि मेरी समझ में इस प्रश्न का उत्तर आंशिक हां के रूप में होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार के कई क्षेत्रों में व्यापार से जुड़े कागजी कार्य में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है। अच्छे रिकॉर्ड रखने वाले लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की अनुमतियां और फॉर्म सबमिशन बहुत आसान हो गए हैं। यह राज्यों और केंद्र स्तर दोनों के संबंध में सच है और इसलिए सुधार समझ में आता है।

हालांकि, इस रेटिंग में सुधार व्यापारिक वातावरण के साथ सुपरिचित लोगों के अनुभवों के साथ संबंधित नहीं है। निर्माण, एक व्यवसाय के रूप में, आमतौर पर करना बहुत आसान नहीं होता है और इसमें सबमिशन, अनुमतियां और यहां तक कि साइड भुगतान की भी आवश्यकता होती है। हालांकि देश भर में कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन इन सुधारों के साथ यह छलांग गैर-अनुरूप प्रतीत होता है। यह संभव है कि भारत रेटिंग 'गेमिंग' कर रहा है। यहाँ रेटिंग गेमिंग का तात्पर्य यह है कि एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी प्रभावी ढंग से सरकार की प्राथमिकताओं को स्थापित कर रही है। ऐसा करना अपेक्षाकृत सरल है।

हांलाकि, इसमें तब तक कुछ गलत नहीं है जब तक कि यह केवल एक संख्यात्मक सुधार ना होकर व्यावसायिक परिस्थितियों में वास्तविक सुधार की ओर अग्रसर है।

अब लेखक कहते हैं कि वे निश्चित रूप से यह कहना नहीं चाहते हैं कि ये सभी चीजें बनावटी हैं। महत्त्वपूर्ण सुधार हो रहे हैं और उनमें से कई सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग के माध्यम से हुए हैं। हम इसे केंद्रीय और राज्य स्तर पर कई सरकारी विभागों में देख सकते हैं। और इन्हीं सब के कारण हाल के वर्षों में इज ऑफ डूइंग बिजनेस में तेजी से सुधार हुआ हैं। इस तरह के सुधार लेनदेन की लागत के मामले में तत्काल प्रभाव डालते हैं। हालांकि, आर्थिक विकास दर पर उनके प्रभाव को लंबे समय तक महसूस किया जाता है – और कभी-कभी किसी भी मापनीय मैक्रो-आर्थिक परिणामों में प्रतिबिंबित होने में कई साल लग सकते हैं। हालांकि, हमें यह समझना चाहिए कि आईटी पर निर्भरता ने उन उद्यमियों के लिए चीजों को और भी मुश्किल बना दिया है जो डिजिटल रूप से कम सक्षम हैं। हांलाकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सब समय और परिस्थितियों के साथ बदल जाएगा, लेकिन इसके लिए सरकार को अपने आईटी-सक्षम इंटरफेस को छोटे और सूक्ष्म व्यापार उद्यमी के लिए अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने में लगातार काम करते रहना होगा।

यह मेक इन इंडिया के बारे में क्या कहता है? प्रक्रिया में परिवर्तन, जो सर्वेक्षण में शामिल थे दीर्घ अवधि में प्रभाव डालेगा और निवेश पर अल्पकालिक प्रभाव तथा नए व्यापार और रोजगार में वृद्धि सीमित हो जाएँगी। ये व्यापक आर्थिक परिस्थितियों, श्रम जलवायु, मांग की स्थिति, बुनियादी ढांचे के मुद्दों आदि से अधिक प्रेरित हैं।

लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ऐसे कई और मुद्दे है जिसे इस रैंकिंग में शामिल नहीं किया जाता है।

जिसमें सबसे पहला है, वे व्यापार के दैनिक चलन से संबंधित बाह्य प्रक्रिया, राजस्व विभाग द्वारा किए गए विभिन्न जांच या कंपनी कानून मामलें या श्रम से संबंधित मुद्दें या गुणवत्ता और प्रक्रियाओं के निरीक्षकों की विभिन्न मांगों को शामिल नहीं करते हैं। परिवर्तन जो ऐसे इंस्पेक्टर राज से दूर हो सकते हैं उसे प्रौद्योगिकी संचार से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कई नियमों और विनियमों और एक दुर्बल प्रेरित नौकरशाही और तकनीकी पर अधिक निर्भरता पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। भारत कई दशकों से इन मुद्दों को हल करने में अनिच्छुक रहा है क्योंकि इसमें सरकार के भीतर और बाहर दोनों समूहों द्वारा गंदी राजनीति खेली जाती है।

दूसरा, भारत में व्यापार की वास्तविकता के लिए उद्यमी को ऐसे मूल्यांकनों की पूरी श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो ऐसी रेटिंग में पर्याप्त रूप से शामिल न हों। मिसाल के तौर पर, व्यवसायों में रोजगार की कमी, खराब कौशल, भ्रष्टाचार और नियंत्रण की समस्या व्याप्त है और साथ ही आंतरिक व्यापार पर नियंत्रण, छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों के लिए पूंजी तक पहुंच की समस्या भी कुछ अन्य उदाहरण हैं। इनमें से कुछ मुद्दे भारत-विशिष्ट हैं और वैश्विक तुलनीयता रेटिंग शायद ही कभी गहराई से इन पर ध्यान देती है।

तीसरा, इनपुट लागत, मांग कारक और आधारभूत संरचना मुद्दे कारकों की एक और श्रेणी है जो व्यवसाय करने में आसानी को पकड़ने का इरादा नहीं रखती है। हालांकि यह अपने फोकस को बनाए रखने में सक्षम बनाता है, ये महत्त्वपूर्ण कारक हैं जो वैश्विक और घरेलू निवेश दोनों को प्रभावित करते हैं।

संक्षेप में, इज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग के अनुसार हुए सुधारों का स्वागत है और यह राज्य एवं केंद्र सरकारों दोनों के बीच होने वाले बदलावों की पुष्टि भी करता है। हालांकि, भारत के आर्थिक माहौल में सुधार के उद्देश्य से सरकार को बहुत कठिन कार्य करने की आवश्यकता है, जिनमें से कुछ रेटिंग में तो शामिल हैं, लेकिन कई नहीं हैं। आखिरकार, जब हम सुधार करने में सक्षम हैं और इसका जश्न मना सकते हैं, तो फोकस और प्राथमिकता भारत के लिए प्रासंगिक मुद्दों पर रहना चाहिए, जो रेटिंग में शामिल नहीं है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में विश्व बैंक की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट में भारत ने 23 स्थानों की जबरदस्त छलांग लगाते हुए 77वां स्थान हासिल किया है।
- विश्व बैंक ने 31 अक्टूबर, 2018 को वैश्विक कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) रिपोर्ट जारी की। भारत का यह रैंकिंग अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
- दस में से 8 मानकों में भारत की स्थिति सुधरी है।
- दरअसल, पिछले वर्ष 190 देशों की सूची में भारत को पहली बार शीर्ष 100 में जगह मिली थी।
- पिछले 2 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रैंकिंग में सुधार करने वाले टॉप 10 देशों में भारत भी शामिल है।
- दक्षिण एशियाई देशों में भारत की रैंक फर्स्ट है। इससे पहले साल 2014 में भारत 6वें स्थान पर था।

क्या है?

- ईज ऑफ डूईंग बिजनेस से तात्पर्य है कि देश में कारोबार करने में कारोबारियों को कितनी आसानी होती है।
- कारोबार के नियामकों और उनके नियमों के अनुसार 10 मानकों पर कारोबार करने की शर्तों को देखा जाता है कि किसी देश में ये कितना आसान या मुश्किल है।
- डूईंग बिजनेस रैंकिंग डिस्टेंस टू फ्रंटियर (डीटीएफ) के आधार पर तय किया जाता है और ये स्कोर दिखाता है कि वैश्विक मानकों पर अर्थव्यवस्था कारोबार के मामले में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
- वर्ष 2018 में भारत का डीटीएफ स्कोर पिछले साल के 60.76 से बढ़कर 67.23 पर आ गया है।

दुर्लभ उपलब्धि

- भारत द्वारा 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में लगाई गई 23 पायदानों की ऊंची छलांग निश्चिततौर पर महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि पिछले वर्ष इस सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में 30 पायदानों की जबर्दस्त छलांग लगाई थी जो भारत के आकार वाले किसी भी विशाल एवं विविधतापूर्ण देश के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है।

मुख्य बिंदु

- कारोबार सुगमता रैंकिंग में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। उसके बाद क्रमशः सिंगापुर, डेनमार्क और हांगकांग का नंबर आता है।
- सूची में अमेरिका आठवें, चीन 46वें और पाकिस्तान 136वें स्थान पर है। विश्व बैंक ने इस मामले में सबसे अधिक सुधार करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत को दसवें स्थान पर रखा है।
- भारत ने दो वर्षों में अपनी रैंकिंग में 53 पायदानों की ऊंची छलांग लगाई है जो डूइंग बिजनेस आकलन में वर्ष 2011 के बाद किसी भी बड़े देश द्वारा दो वर्षों में किये गये सर्वाधिक बेहतरी को दर्शाता है।

कैसे तय होती है यह रैंकिंग?

- भारत ने वर्ष 2003 से अब तक 37 बड़े सुधार लागू किए हैं। इस रिपोर्ट में वर्ष 2017 में दिल्ली और मुंबई को शामिल किया गया था।
- रिपोर्ट में किसी कारोबार को शुरू करना, कंस्ट्रक्शन परमिट, क्रेडिट मिलना, छोटे निवेशकों की सुरक्षा, टैक्स देना, विदेशों में ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट लागू करना और दिवालिया शोधन प्रक्रिया को आधार बनाया जाता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस रैंकिंग में भारत पिछले दो वर्षों से निरंतर सुधार दर्ज कर रहा है।
2. इस रैंकिंग का निर्धारण दस श्रेणियों के आधार पर किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

2. इज ऑफ डूइंग बिजनेस सर्वे-2019 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की कौन-सी रैंकिंग निर्धारित की गयी है?

(a) 130 वीं (b) 100 वीं
(c) 23 वीं (d) 77 वीं

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. हाल के कुछ वर्षों से भारत इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार कर रहा है जो इसे निर्धारित करने वाले श्रेणियों में हो रहे सुधार को दर्शाता है। क्या आपको लगता है कि भारत को अभी इन श्रेणियों में और सुधार की आवश्यकता है? न्याय संगत उत्तर दीजिए। (शब्द-250)

नोट :
3 नवम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(c) और 3(b) होगा।